ल.अं./52/एसएलबीसी/दिसंबर 2025/ 180

दिनांक : 08.04.2026

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ. प्र.) के समस्त सदस्यों को पत्र

महोदय,

विषय : **राज्य स्तरीय बैकर्स समिति (उ.प्र.) की दिसंबर 2025 त्रैमासांत की बैठक दिनांक 19.03.2026 का कार्यवृत्त**

कृपया दिनांक **19.03.2026** को सम्पन्न राज्य स्तरीय बैकर्स समिति (उ.प्र.) की दिसंबर 2025 को समाप्त तिमाही की समीक्षा बैठक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उपरोक्त बैठक का कार्यवृत्त एवं कार्यवाही बिन्दु आपकी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित है।

भवदीय,

शैलेन्द्र कुमार सिंह

(शैलेंद्र कुमार सिंह)
महाप्रबंधक एवं संयोजक
राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ0प्र0)

संलग्नक : उपरोक्तानुसार

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ. प्र.) की दिसंबर 2025 तिमाही की बैठक
दिनांक 19.03.2026 का कार्यवृत्त

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ.प्र.) की दिसंबर 2025 त्रैमासिक समीक्षा बैठक दिनांक 19.03.2026 को **"मुख्य सचिव सभागार", लोक भवन, हजरतगंज, लखनऊ** में सम्पन्न हुई जिसकी अध्यक्षता श्री एस. पी. गोयल, आई.ए.एस., मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन एवं सह - अध्यक्षता श्री लाल सिंह, कार्यपालक निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा, मुम्बई द्वारा की गयी।

बैठक में श्री पंकज कुमार, क्षेत्रीय निदेशक, RBI, लखनऊ; श्री चंद्रदीप कुमार झा, डिप्टी डायरेक्टर जनरल, वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार (वीसी के माध्यम से); श्री रवीन्द्र, प्रमुख सचिव, कृषि, उ.प्र.; श्रीमती संदीप कौर, महानिदेशक, संस्थागत वित्त, उ.प्र.; श्रीमती अपूर्वा दुबे, निदेशक, SUDA; श्री इंद्रजीत सिंह, निदेशक, UPNEDA; श्री जयनाथ यादव, एएमडी, UPSRLM; श्री पंकज कुमार, मुख्य महाप्रबंधक, NABARD, लखनऊ; श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह, महाप्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा एवं संयोजक, एस.एल.बी.सी. (उ.प्र.); श्री जय कुमार गुप्ता, महाप्रबंधक, सिडबी, लखनऊ; सहित राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण तथा बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं के वरिष्ठ अधिकारीगणों द्वारा सहभागिता की गई। बैठक में भाग लेने वाले सहभागियों की सूची संलग्न है।

बैठक के प्रारम्भ में **श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह, महाप्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा एवं संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ.प्र.)** ने सभी सम्मानित सदस्यों का स्वागत करते हुए वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान प्रदेश में गठित कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियों से सभा को निम्नवत अवगत कराया :

❖ सर्वप्रथम उन्होने दिनांक 01.02.2026 को माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में आयोजित एसएलबीसी की समीक्षा बैठक के महत्वपूर्ण कार्यवाही बिन्दुओ से सभा को अवगत कराया :

1) प्रदेश का ऋण जमानुपात मार्च 2026 तक 62% तक पहुंचाने हेतु ऐसे बैंक जिनका ऋण जमानुपात 60% से कम है, के ऋण जमानुपात को प्रदेश के औसत के अनुरूप बढ़ाने हेतु कार्ययोजना तैयार कर आवश्यक एवं प्रभावी प्रयास करने के साथ साथ ऐसे बैंक जिनका ऋण जमानुपात 50% से कम है, बैंक विशेष ऋण मेला का आयोजन करते हुए लक्ष्यानुरूप प्रगति सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है ।

2) सीएम युवा योजना, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना तथा पीएम स्वनिधि योजना सहित विभिन्न सरकार प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों को प्राथमिकता के आधार पर ऋण उपलब्ध कराए जाने तथा लंबित आवेदन पत्रो का शीघ निस्तारण किए जाने हेतु आह्वाहन किया ।

❖ दिनांक 09 से 13 फरवरी 2026 तक वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया गया, जिसका विषय "KYC - सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम" था। इस दौरान बैंको द्वारा "KYC- आपकी पहचान, आपकी सुरक्षा", सही KYC, मजबूत साइबर सुरक्षा" तथा "CKYC से आसान, तेज एवं सुरक्षित बैंकिंग" संबंधी जागरूकता संदेश प्रसारित किए गए।

❖ दिनांक 20 फरवरी 2026 को प्रदेश के समस्त जनपदो में ऋण शिविरों का आयोजन किया गया जिसमे ₹ 7,100 करोड़ से अधिक के ऋण वितरित किए गए। आगामी 18 एवं 25 मार्च 2026 को पुनः प्रदेश के समस्त जनपदो में ऋण शिविर आयोजित किए जाएंगे। बैंको से अनुरोध किया कि इन ऋण शिविरों में सहभागिता सुनिश्चित करें।

❖ उत्तर प्रदेश में साइबर धोखाधड़ी से संबंधित धनराशि रोकने हेतु CFMC, लखनऊ स्थापित किया गया है, जिसमें अब तक 18 बैंकों के अधिकारियों को नियुक्त किया जा चुका हैं। तृतीय चरण में 5 अन्य बैंकों यथा - केनरा बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, आईडीबीआई बैंक, यस बैंक तथा बंधन बैंक के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति प्रस्तावित है। सभी संबंधित बैंकों से अनुरोध है कि CFMC के सुचारु संचालन हेतु आवश्यक सहयोग सुनिश्चित करें।

❖ वार्षिक ऋण योजना 2025-26 के अंतर्गत आवंटित लक्ष्यों ₹ 6.45 लाख करोड़ के सापेक्ष दिसम्बर 2025 तिमाही तक कुल ₹ 4.25 करोड़ (66%) की उपलब्धि दर्ज की गई है। एमएसएमई क्षेत्र में ₹ 3.66 लाख करोड़ के लक्ष्य के सापेक्ष ₹ 2.57 लाख करोड़ (70%) तथा कृषि क्षेत्र में ₹ 2.43 लाख करोड़ के लक्ष्य के सापेक्ष ₹1.53 लाख करोड़ (63%) की उपलब्धि रही।

❖ प्रदेश का ऋण जमानुपात दिसम्बर 2025 में 60.39% पहुंच गया है। साथ ही 40% से कम ऋण जमानुपात वाले जनपदों की संख्या भी मार्च 2025 के स्तर 7 से घटकर दिसम्बर 2025 मे 5 रह गई है।

अपने सम्बोधन में **श्री लाल सिंह, कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा** ने सभागार में उपस्थित सभी अतिथियों का अभिवादन करते हुए समिति को निम्न महत्वपूर्ण गतिविधियो से अवगत कराया :

❖ वर्ष 2026-27 का केंद्रीय बजट युवाओं, निवेश एवं समावेशी विकास पर केन्द्रित है। इस वर्ष पूंजीगत व्यय को बढ़ाकर ₹17.14 लाख करोड़ किया जाना सरकार की मजबूत अवसंरचना निर्माण एवं दीर्घकालिक आर्थिक सुदृढ़ता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। बजट में बुनियादी ढांचे, विनिर्माण एवं डिजिटल नवाचार को प्राथमिकता दी गई है, जो देश की विकासात्मक आकांक्षाओं को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण है।

❖ बैंकिंग क्षेत्र के लिए यह बजट विशेष महत्व रखता है। "विकसित भारत 2047" के दृष्टिकोण से बैंकिंग प्रणाली की समीक्षा हेतु उच्च-स्तरीय समिति का प्रस्ताव एक महत्वपूर्ण पहल है, जिससे वित्तीय समावेशन, डिजिटल सेवाओं की पहुंच, तथा MSME, कृषि एवं उद्योग क्षेत्रों को समयबद्ध ऋण उपलब्धता को बल मिलेगा।

❖ डिजिटल बैंकिंग, फिनटेक एवं साइबर सुरक्षा को सुदृढ़ करने पर भी विशेष जोर दिया गया है। केंद्रीय एवं राज्य बजट दोनों ही समावेशी विकास, अवसंरचना विस्तार, कृषि सुदृढ़ीकरण एवं रोजगार सृजन पर केंद्रित हैं, जो बैंकों के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश प्रदान करते हैं। बैंकों को "क्रेडिट प्लस अप्रोच" अपनाते हुए ऋण के प्रभावी उपयोग एवं परिणामों पर ध्यान देना अपेक्षित है।

❖ माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में आयोजित SLBC बैठक दिनांक 01.02.2026 के दौरान विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों को गुणवत्तापूर्ण एवं समुचित प्रशिक्षण प्रदान किए जाने पर विशेष बल दिया गया जिसका मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक लाभार्थियों को प्रशिक्षित कर उन्हें दक्ष एवं आत्मनिर्भर बनाना तथा Micro Entrepreneurship को प्रोत्साहित करना है।

❖ बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा "ODOP" योजना को "ODOP- Next Gen" के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए गए तथा बैंकों को इसमें सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित कर उद्यमियों को बेहतर वित्तीय सहयोग प्रदान करने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

❖ साथ ही, “ODOC - One District One Cuisine” योजना के शुभारंभ के साथ बैंकों को लाभार्थियों को आवश्यक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने में सक्रिय सहयोग हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

❖ वित्तीय वर्ष 2025-26 दिसंबर तिमाही के अंत में सभी बैंक का कुल व्यवसाय रू 32.79 लाख करोड़ पहुंच गया है।

❖ बैंको ने जमा मे 10.01% एवं अग्रिम में 11.39% की Y-o-Y Growth की है।

❖ प्रदेश का ऋण जमानुपात दिसंबर 2025 मे 60.39% के स्तर पर पहुंच गया है।

❖ Advances to Priority Sector ने 14.58% की Y-o-Y Growth की है। Agriculture Advances में 5.35% एवं MSME Advances में 23.18% की Y-o-Y Growth की है।

अपने सम्बोधन के अंत में उन्होने सभा में उपस्थित सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए सार्थक चर्चा हेतु बधाई दी।

श्री पंकज कुमार, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ ने सभी प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए अपने संबोधन में निम्न बिन्दुओं से अवगत कराया :

❖ प्रदेश की जीएसडीपी वृद्धि 9% (2024-25) रही है, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था ₹ 29.80 लाख करोड़ से बढ़कर ₹36 लाख करोड़ होने का अनुमान है।

❖ दिसंबर 2025 मे प्रदेश का ऋण जमानुपात बढ़कर 60.39% के स्तर पर पहुंच गया है। 40% से कम ऋण जमानुपात वाले जनपदो की संख्या भी सितंबर 2025 के स्तर 6 जनपदो से घटकर दिसंबर 2025 में 5 जनपद रह गई है।

❖ वार्षिक ऋण योजना 2025-26 के अंतर्गत दिसंबर 2025 तक 65.82% उपलब्धि दर्ज की गई। MSME क्षेत्र के अंतर्गत प्रदर्शन संतोषजनक रहा, जबकि कृषि क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता है।

❖ प्रदेश के कुल एनपीए में वृद्धि एवं वसूली से संबंधित चुनौतियों पर चिंता व्यक्त की।

❖ वित्तीय समावेशन के अंतर्गत Re-KYC लगभग 48% पूर्ण किया गया। प्रदेश द्वारा पैन इंडिया सर्वाधिक- 57695 ग्राम पंचायतों मे कैंपो का आयोजन किया। उन्होने बैंको से अनुरोध किया कि re-KYC हेतु due खातो के लक्ष्यो को हासिल करने के लिए रणनीति बनाते हुए आवश्यक प्रयास करें।

❖ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संचालित तकनीकी प्लेटफ़ॉर्म -Unified Lending Interface (ULI) पर राजस्व विभाग, उ प्र के साथ समन्वय करते हुए भूमि एकीकरण की प्रक्रिया का कार्य किया जा रहा है। राजस्व विभाग द्वारा प्राप्त अद्यतन स्थिति के अनुसार उक्त प्लेटफॉर्म पर flag marking system न केवल रू 2 लाख तक के कृषि ऋणों के लिए, बल्कि रू 10 लाख तक के कृषि ऋणों के लिए भी लागू है। अर्थात रू 10 लाख तक के ऋण बिना किसी संपार्श्विक प्रतिभूति के प्राप्त हो सके जो मौजूदा नियमों के अनुरूप नहीं है। उक्त प्रकरण मे संशोधन किया जाना लंबित है। राजस्व विभाग से अनुरोध है कि इस प्रस्ताव को शीघ्रता से पारित किया जाए ताकि यह आदेश मौजूदा दिशा निर्देशों के अनुरूप हो सके।

(कार्यवाही : राजस्व विभाग, उ. प्र.)

- ❖ साथ ही CM Yuva Yojana को भी ULI से integrate किए जाने की प्रक्रिया जारी है ताकि योजना के लाभार्थियो को आसानी से कम समय मे ऋण प्राप्त हो सके। ULI का उपयोग दो चरणों यथा सीएम युवा पोर्टल से आवेदक द्वारा चुने गए बैंक को आवेदन भेजना और बैंकों द्वारा ऋण आवेदनों की स्वीकृति हेतु प्रक्रिया पर सहमति बनी है। बैंकों को ULI के माध्यम से ऋण प्रदान किए जाने हेतु निर्देशित किया।

- ❖ राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन रणनीति (NSFI 2025-30) के तहत डिजिटल भुगतान, महिला बीसी की संख्या में वृद्धि एवं अंतिम छोर तक बैंकिंग सेवाओं के विस्तार पर बल दिया गया। SLBC एवं सभी सदस्य बैंकों से अनुरोध है कि समयबद्ध कार्ययोजना तैयार कर उसको कार्यान्वित करें तथा नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करें। साथ ही ATRs पर कार्यवाही निर्धारित समयावधि में करें।

(कार्यवाही - एस.एल.बी.सी., उ.प्र. एवं समस्त सदस्य बैंक)

श्री पंकज कुमार, मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, लखनऊ ने अपने संबोधन में बैठक में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों का स्वागत करते हुए सदन को निम्न बिन्दुओं से अवगत कराया:

- ❖ वार्षिक ऋण योजनान्तर्गत एमएसएमई क्षेत्र में लक्ष्यो के सापेक्ष प्रगति कि रिपोर्टिंग भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के दिशानिर्देशों के अनुरूप तथा CGTMSE व MSME Act के अनुसार ही किए जाने का अनुरोध किया।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

- ❖ प्रदेश के सभी जनपदो में ग्रामों की मैपिंग शाखाओ से किए जाने हेतु अनुरोध किया। यह कार्य पूर्व मे भी 2014 में किया जा चुका है।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

- ❖ PM Kisan के लाभार्थियों एवं बैंकों द्वारा दिए गए केसीसी के आंकड़ों में मिलान किया जाना अत्यंत आवश्यक है जिससे कि प्रदेश में केसीसी से वंचित किसानों की पहचान कर उन्हें किसान क्रडिट कार्ड से आछादित किया जा सके।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

- ❖ सभी अग्रणी जिला प्रबन्धकों से अनुरोध किया कि वित्त वर्ष 2026-27 हेतु तैयार कि जा रही वार्षिक ऋण योजना के लक्ष्यों को 2026-27 के पीएलपी अनुमानों के साथ संरेखित करें।

(कार्यवाही: समस्त अग्रणी बैंक एवं अग्रणी जिला प्रबन्धक)

- ❖ RSETIs के द्वारा प्रशिक्षित किये जा रहे लाभार्थियों को प्रदेश सरकार की सीएम युवा योजना के तहत क्रेडिट लिंकेज किये जाने हेतु विशेष प्रयास किये जाने कि आवश्यकता है।

- ❖ अग्रणी बैंक योजना के अंतर्गत वार्षिक ऋण योजना में कृषि क्षेत्र की संबद्ध गतिविधियों (Allied Activities) की प्रगति का पृथक रूप से रिपोर्टिंग किया जाना आवश्यक है। इससे इस क्षेत्र में वितरित ऋण की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित की जा सकेगी तथा बेहतर ऋण नियोजन और लक्ष्य निर्धारण में भी सहायता प्राप्त होगी।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

बैंक ऑफ बड़ौदा BANK OF BARODA राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति उ0 प्र0 Zonal Office (Lucknow Zone), Lucknow

पॉवर प्वाइंट प्रस्तुति :

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की दिनांक 10.12.2025 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि :

- ✓ सितंबर 2025 त्रैमास की बैठक दिनांक 10.12.2025 के कार्यबिन्दु एवं कार्यवृत्त सभी सदस्यों को एस.एल.बी.सी. के पत्रांक ल.अं./51/एस.एल.बी.सी./सितंबर 2025/664 दिनांक 22.12.2025 के माध्यम से प्रेषित किये गये थे, जिसकी पुष्टि समिति द्वारा की गयी।

- ✓ सर्वप्रथम गत एसएलबीसी की बैठक के दौरान उभरे कार्यवाही बिन्दुओ पर विस्तृत चर्चा की गई एवं शीघ्र निरस्तारण हेतु संबन्धित विभागो से अनुरोध किया गया।

- ✓ बैंकिंग संबंधी महत्वपूर्ण संकेतको यथा जमा, अग्रिम, ऋण जमानुपात, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, कृषि एवं एमएसएमई के अंतर्गत अग्रिम इत्यादि से अवगत कराया गया।

- ✓ राजस्व विभाग द्वारा चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत आर सी पोर्टल पर बैंको द्वारा वसूली धनराशि अद्यतन किया जाना अपेक्षित है जिसके फलस्वरूप प्रदेश मे आर सी खातो की संख्या एवं धनराशि मार्च 2025 के स्तर 10.70 लाख खाते (₹ 20,044 करोड़) से घटकर दिसंबर 2025 में 9.38 लाख खाते (₹ 19,930 करोड़) पहुंच गई है। बैंको से अनुरोध किया कि ऐसे खाते जिनमे वसूली की जा चुकी है, की स्थिति पोर्टल पर अवश्य अपडेट करें ताकि वास्तविक स्थिति परिलक्षित हो सके।

(कार्यवाही:समस्त सदस्य बैंक)

- ✓ सरफेसी खातो की संख्या एवं धनराशि मार्च 2025 के स्तर 4,833 खाते (₹ 1,706 करोड़) से घटकर दिसंबर 2025 में 4714 खाते (₹ 1,743 करोड़) पहुंच गई है।

- ✓ वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 5 New Unbanked Villages की सूची प्रेषित की गई जिन्हे बैंको को शाखा खोलने हेतु आवंटित किया जा चुका है। ग्राम किलौहा, महोबा (केनरा बैंक) मे 22.10.2025 को तथा ग्राम रानाहोर, सोनभद्र (इंडियन ओवरसीज बैंक) मे 31.12.2025 को शाखा खोली जा चुकी है। ग्राम मड़ैया, चित्रकूट (भारतीय स्टेट बैंक), ऊंचाडीह, चित्रकूट (बैंक ऑफ बड़ौदा) तथा अकथौहा, महोबा (यूनियन बैंक ऑफ इंडिया) मे शाखा खोलने की कार्यवाही लंबित है। अद्यतन स्थिति के अनुसार लंबित केन्द्रों पर सम्बंधित बैंक से अग्रणी जिला प्रबंधक के माध्यम से सम्बंधित जिलाधिकारीयों से आवश्यक सहयोग प्राप्त करने एवं अतिशीघ्र शाखा खोलने की कार्यवाही करने हेतु अनुरोध है।

(कार्यवाही: संबन्धित बैंक)

श्री एस. पी. गोयल, आई.ए.एस., मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी बैंकों को संबोधित करते हुए निम्नानुसार निर्देशित किया :

- ❖ उन्होंने प्रधानमंत्री जनधन योजना को प्रदेश में प्रभावी रूप से लागू करने हेतु सभी बैंकों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि सतत वित्तीय विकास सुनिश्चित करने के लिए बैंकों को ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति बढ़ानी होगी तथा सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ करना आवश्यक है। साथ ही उन्होंने निर्देश दिया कि जिन केंद्रों पर अभी Brick &

- ❖ Mortar शाखाएँ उपलब्ध नहीं हैं, वहाँ आवंटित बैंक शीघ्र उपयुक्त स्थान/भवन चिन्हित कर बिना विलंब शाखाएँ खोलने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

- ❖ उन्होंने सभी बैंकों से अपेक्षा की कि वे प्रदेश के समग्र विकास में सक्रिय भागीदारी निभाते हुए केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में सहयोग करें। जिन बैंकों द्वारा उक्त योजनाओं में संतोषजनक प्रगति नहीं प्राप्त की जाएगी , ऐसे बैंकों में जमा सरकारी जमा धनराशि को योजना में अच्छी प्रगति करने वाले बैंकों में स्थानांतरित करने पर शासन स्तर से निर्णय लिया जाएगा।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

- ❖ प्रदेश में कार्यरत बैंकों से सम्बंधित विभिन्न जनपदों में लंबित मुद्दों - जैसे आरसी पोर्टल पर दर्ज ऋण वसूली के प्रकरण, सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत वसूली हेतु जिलाधिकारी स्तर पर लंबित मामले, RSETI के लिए वैकल्पिक भूमि आवंटन से संबंधित प्रकरण, B&M शाखाएँ खोलने हेतु चिन्हित केंद्रों पर प्रगति की स्थिति तथा केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लंबित आवेदनों की नियमित समीक्षा जिलाधिकारी के साथ आयोजित होने वाली साप्ताहिक बैठकों में विस्तृत चर्चा की जाए, ताकि लंबित प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण हो सके।

- ❖ उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि आगामी बैठकों में, यदि संभव हो, तो विभिन्न महत्वपूर्ण आंकड़े जैसे प्रति व्यक्ति खातों की संख्या, प्रति लाख जनसंख्या पर प्रधानमंत्री जनधन खातों की उपलब्धता, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की प्रगति, राशि के अनुसार बकाया ऋण खातों की संख्या तथा अन्य संबंधित मानकों को भी प्रस्तुत किया जाए। इससे प्रदेश में वित्तीय समावेशन एवं ऋण वितरण की प्रगति की अधिक प्रभावी एवं समग्र समीक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी।

बैठक में चर्चा के दौरान **श्री रवीन्द्र, प्रमुख सचिव, कृषि, उ.प्र. शासन** ने अपने सम्बोधन में कहा कि निम्न मुख्य बिन्दुओ से अवगत कराया

- ❖ केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं को जनमानस तक प्रभावी रूप से पहुँचाने हेतु नोडल विभागों एवं सभी बैंकों को समन्वित प्रयास करने होंगे। साथ ही, योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है, ताकि लौटाए जाने वाले आवेदनों की संख्या में कमी लाई जा सके।

(कार्यवाही: समस्त नोडल एजेंसी एवं सदस्य बैंक)

- ❖ उन्होंने सभी बैंकों को दिनांक 10 दिसम्बर, 2025 को आयोजित बैठक में दिए गए निर्देशानुसार खरीफ 2025 मौसम में जिन के०सी०सी० धारक कृषकों का फसल बीमा नहीं किया गया है, उन खाताधारकों का बैंक शाखा वार विवरण, बीमा न किये जाने के कारण सहित, कृषि सांख्यिकी एवं फसल वीमा विभाग, उत्तर प्रदेश को तुरंत उपलब्ध कराये जाने हेतु पुनः निर्देशित किया। उक्त सूचना शासन द्वारा कृषि सांख्यिकी एवं फसल वीमा विभाग, उत्तर प्रदेश एवं एसएलबीसी के माध्यम से निरंतर सभी बैंकों से मांगी जा रही है किन्तु अभी भी अधिकतर बैंकों से प्राप्त नहीं हुई है।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

श्रीमती संदीप कौर, आई.ए.एस., महानिदेशिका, संस्थागत वित्त एवं बाह्य सहायतित विभाग, उ. प्र. शासन ने अपने सम्बोधन में निम्न मुख्य बिन्दुओ से अवगत कराया :

- ❖ केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं जैसे PM Vishwakarma, CM YUVA, PM Suryaghar, PMFME आदि के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों में लौटाए जाने वाले आवेदनों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक है। अतः सभी

❖ नोडल विभाग आवेदन पत्रों की गुणवत्ता में सुधार सुनिश्चित करें तथा दस्तावेज़ों की पूर्णता एवं पात्रता की पूर्व जांच पर विशेष ध्यान देते हुए बैंकों को प्रेषित करें, जिससे बैंक स्तर से निरस्त/लौटाए जाने वाले आवेदनों की संख्या में कमी लाई जा सके तथा अधिक से अधिक लाभार्थियों को ऋण उपलब्ध कराया जा सके।

❖ सामाजिक सुरक्षा योजना – PMJJBY के अंतर्गत प्रदेश में किए गए कुल नामांकनों में से अधिकतम संख्या में सक्रिय रखने हेतु आमजन को योजना के लाभों के प्रति नियमित रूप से जागरूक करने हेतु बैंकों द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार एवं जनजागरूकता अभियान संचालित किए जाने चाहिए, जिससे अधिकाधिक लोग योजना से जोड़कर इसका लाभ निरंतर प्राप्त हो सकें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

श्री इंद्रजीत सिंह, आई.ए.एस., निदेशक, यूपीनेडा, उत्तर प्रदेश ने अपने सम्बोधन में निम्नवत अवगत कराया :

❖ सर्वप्रथम उन्होंने प्रदेश में प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत किए गए सोलर इंस्टालेशन में प्रदेश के पैन इंडिया अग्रणी स्थान प्राप्त करने पर समस्त बैंकर्स को बधाई दी। साथ ही उन्होंने वर्तमान वित्त वर्ष के समापन एवं आगामी वित्त वर्ष की प्रथम तिमाही के दौरान इस योजना के अंतर्गत लंबित तथा प्राप्त होने वाले सभी नए आवेदनों पर बिना किसी विलंब के शीघ्र ऋण वितरण सुनिश्चित किए जाने का अनुरोध किया।

❖ पी. एम. कुसुम योजना के C2 कॉम्पोनेन्ट के अंतर्गत प्रदेश में सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि को बढ़ावा देने हेतु लंबित ऋण आवेदन पत्रों के त्वरित निस्तारण के लिए बैंकों से आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

✓ RSETIs के बीपीएल दावों की प्रतिपूर्ति हेतु दिसंबर 2025 तक रू 131.32 करोड़ की धनराशि लंबित है। विभाग के पत्र दिनांक 12.02.2026 के माध्यम से रू 20 करोड़ की क्लेम राशि released की जा चुकी है। एक बार पुन: यूपीएसआरएलएम प्रतिनिधि से अनुरोध किया कि लंबित क्लेम धनराशि की प्रतिपूर्ति अतिशीघ्र बैंको को देने हेतु कार्यवाही करें ताकि आरसेटी निर्बाध रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन कर सके।

(कार्यवाही: यू.पी.एस.आर.एल.एम. विभाग)

✓ प्रदेश मे 7 जनपद RSETI- वैकल्पिक भूमि आवंटन हेतु लंबित है। सदन से अनुरोध किया कि संबन्धित बैंक एवं विभाग समन्वय स्थापित कर भूमि आवंटन की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करे।

(कार्यवाही: समस्त बैंक)

✓ **PM SVAMITVA योजना** के अंतर्गत बैंको के प्रधान कार्यालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों को एसएलबीसी के साथ साझा किए जाने हेतु अनुरोध किया गया साथ ही यदि बैंको द्वारा योजनान्तर्गत ऋण प्रदान किए जा रहे है, तो इसकी सूचना त्रैमासिक आधार पर SLBC India Portal एवं साप्ताहिक आधार पर अग्रणी जिला प्रबन्धक को भेजना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

✓ सरकार प्रायोजित विभिन्न योजनाओं यथा CM Yuva, PMFME, PM Surya Ghar, PM Vishwakarma, AIF, ODOP, MYSY इत्यादि में अधिक से अधिक ऋण वितरण किए जाने हेतु अनुरोध किया।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

अंत में बैठक श्रीमती निधि कुमार, उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ.प्र.) के धन्यवाद प्रस्ताव के साथ सम्पन्न हुई।

****

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ,लखनऊ

SLBC QE Dec'25 Meeting 19.03.2026

Participation Sheet

S.no.	Name of Participant	Designation	Name of Organization/ Deptt.	Contact No.	Email id	Signature
1.	Manoj Kumar	Zonal Head	IDBI Bank	7622019804	kumar.manoj@idbi.co.in	
2.	SHWETABH GUPTA	ZONAL MANAGER	UTKARSH SMALL FINANCE BANK	9792014221	shwetabh.gupta@utkarsh.bank	
3.	Amit Mishra	Regional Head	INDUSIND BANK	9044412345	Amit.Mishra3@INDUSIND.com	
4.	A N Singh	ZM	P&SB	9917246207	awdhesh.singh@psb.co.in	
5.	Mrityunjay	Z.M.	PNB	9810509415	Mrityunjay@pnb.co.in	
6.	ANUJ RAJ	Reg. Head	HDFC Bank	7499986270	anuj.raj@hdfcbank.in	
7.	Saif Kazmi	Z.M	ICICI Bank	9792346111	saif.kazmi@icicibank.com	
8.	Ashok Kumar	GM	U.P. Coop Bank Ltd	7525W6031	UPCB IDD.@gmail.com	
9.	जे.बी.यादव	Add. L.R.C	राजस्व परिषद	9634110008		
10.	SUNIL KUMAR PANDEY	MEMBER	NTWB	8840196073 9335318787	SUNILPANDEYBUVM52@gmail.com	
11.	RAJESH KUMAR YADAV	SP-CYBER U.P.	POLICE	9454400581	sp-cyber.ln@up.gov.in	
12.	Arvind Misra	S.P., E.O.W Lucknow	U.P. Police	954400322	arvind.misra777@gmail.com	
13.	Sarveshwar Shukla	Nodal officer CM, YUVA	MSME	9415054007	cmmyuva@gmail.com	
14.	Jaynath yadav	AMD. SRLM SLRD	SRLM/RDD	9450408542	—	
15.	Indujit Singh	Director UPNEDA	Deptt of Add Energy	9878955674		
16.	Dr. Pankaj Tripathi	Director	Agriculture	9415322358	pnjtripathi66@gmail.com	
17.	Sandeep Kaur	Secretary/ संस्थागत, वित्त	finance dept	9456659511		
18.						
19.						
20.						

S.no.	Name of Participants	Designation	Name of Organization/ Deptt.	Contact No.	Email id	Signature
41.	Amit Goyal	Zonal Manager	Bank of Maharashtra	9893003610	zmlucknow@bankofmaharashtra.bank.in	[signature]
42.	Sanjeev Singh Tomar	Chief Manager	UPGB	8109217317	advances.ho@barodaupgb.co.in	[signature]
43.	U.K. Mishra	G.M.	UPGB	7081005001	gmadvances@upgb.bank.in	[signature]
44.	D.K. Arjwani	G.M.	Central Bank of India	8303713863	zmluck30@centralbank.bank.in	[signature]
45.	Amarendra Kumar	GM	BOI	9431623272	FGMO.Lucknow@bankofindia.bank.in	[signature]
46.	AJIT KUMAR MISHRA	GM	CANARA BANK	8570023664	Luckfgo@canarabank.bank	[signature]
47.	P.K. AWASTHI	D.G.M.	Union Bank of India	7888045921	dyzh.lucknow@unionbank	[signature]
48.	Jay Kr. Gupta	GM	SIDBI	7237058888	jaykgupta@sidbi.in	[signature]
49.	Sudhir K. Gupta	CGM	Indian Bank	9909922454	sudhir.gupta@indianbank.bank.in	[signature]
50.	Anil Kumar	GM	State Bank of India	9431384936	gm1.lholuc@sbi.co.in	[signature]
51.	Sunanda Bose	GM	NABARD	7597647324	sunanda.bose@nabard.org	[signature]
52.	Sonali Das	GM	RBI	9836107580	sonalidas@rbi.org.in	[signature]
53.	Prateek Agnihotri	GM	Bank of Baroda	9920013421	gm.waupu@bankofbaroda.com	[signature]
54.	Mithlesh Kumar	GM	Bank of Baroda	7506964044	mithlesh.kumar@bankofbaroda.com	[signature]
55.	Nidhi Kumar	DGM	SLBC		slbc.up@bankofbaroda.com	[signature]
56.	Anupam Dutta	DGM	NABARD	9594115422	anupam.dutta@nabard.org	[signature]
57.	Rajeev Tyagi	Dy CEO	U.P. Khadi & V.I. Board	8383085208	ceoupkvib@gmail.com	[signature]
58.	Alok Srivastava	AGM	SBI	7235809044	alok_s@sbi.co.in	[signature]
59.	ANKKIT GUPTA	SM	Indian Bank	7985180873	FGMO.LUCKNOW@INDIANBANK.BANK.IN	[signature]
60.	Nikhil Prem	Mgr	Nabard	9579515612	cpd.lucknow@nabard.org	[signature]

S.no.	Name of Participants	Designation	Name of Organization/ Deptt.	Contact No.	Email id	Signature
61.	Vibhav Verma	Dy. G.M.	SBI	8349160748	dgmabu.luc440@sbi.co.in	[signature]
62.	Sanjeev Kr Singh	Sr. Manager	BOI	9412575562	fgmo.lucknow@bankofindia.co.in	[signature]
63.	Devesh Pratap Singh	Sr manager	Canara Bank	9455504252	msmecolucknow@canarabank.com	[signature]
64.	Divyanshu Tripathi	Manager	Canara Bank	7706991580	lucknowco@canarabank.com	[signature]
65.	Anil Kr. Singh	Add. Regi. (B) Cooperative	Cooperatives	9793987200		[signature]
66.	Apurva Dubey	Dir SUDA	SUDA			[signature]
67.	Aishwarya Gupta	Manager	IOB	9795443845	0814pcdagri@iob.in	[signature]
68.	Syed Abdul Khader	Ambalam (DGM)	IOB	9952033415	"	[signature]
69.	Rathijit Gupta	Sr. Manager	Bank of Maharashtra	9831237994	cragr_luc@bankofmaharashtra.bank.in	[signature]
70.						
71.						
72.						
73.						
74.						
75.						
76.						
77.						
78.						
79.						
80.						